>

Title: Need to announce support price for mustard.

श्री भँवर सिंह डांगावास (नागौर) : सभापति महोदय, किसानों की फसलों के लिए समर्थन मूल्य बहुत कम रखा जाता है। इसके बारे में जब स्वामीनाथन कमीशन बैठा था, तब उसने कहा था कि उपज पैदा करने के खर्च में 40 प्रतिशत राशि जोड़कर समर्थन मूल्य रखना चाहिए। अभी हाल की बात यह है कि सरसों जिसे हम (राइड़ा) कहते हैं, उसका समर्थन मूल्य बहुत कम है और बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं है।

अतः मेरी प्रार्थना है कि हमारी लागत एक क्विंटल पर दो हजार रुपये आती है, उसके ऊपर चालीस परसैन्ट देकर 2800 रुपये समर्थन मूल्य तय किया जाए और इसकी खरीदारी जल्दी की जाए।

* यदि इस प्रकार सब जिन्सों का समर्थन मूल्य रखा जाए तो किसान पर किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं चढ़ेगा, न ही से भुखमरी की नौबत आएगी।

आज जो हालत रबी फसल सरसों (राईड़ा) के पूरी कीमत नहीं मिलने के कारण किसान घाटे में हैं और सालों साल इस प्रकार घाटे में रहने के कारण ऋण के बोझ से लद जाता है।

मैं राईड़ा (सरसों) की फसल के बारे में श्रीमान् के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। अब यह फसल पक कर मंडियों में बिकने आ चुकी है। इसे जब बोया था तब कीमत थी 2700-2800 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि अब बिक रही है 1600-2000 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि समर्थन मूल्य रुपये 1850/- प्रति क्विंटल है जो कतई लाभप्रद नहीं है। इस फसल की प्रति क्विंटल पैदावार करने में 2000/- रुपये खर्च होते हैं। डाक्टर स्वामीनाथन के आयोग के हिसाब से कीमत 2000/- + (40 प्रतिशत=800) - कुल रुपये 2800/- होने चाहिए। तब कहीं जाकर किसान के लाभप्रद होती है।

इसके अलावा भी जो समर्थन मूल्य है, उस पर सरकार खरीद की व्यवस्था नहीं करती है। आज तक कोई समर्थन मूल्य पर खरीद मंडियों में हो नहीं रही है। अगर समर्थन मूल्य पर खरीदारी होती है तो व्यापारी भी इसे समर्थन मूल्य से कुछ अधिक राशि पर खरीदना प्रारंभ करते हैं।

आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि समर्थन मूल्य रुपये 2800/- मुकर्रर करें और फसल पकते ही इस समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंडियों में व्यवस्था करवाएं।

अगर यह हो जाएगा तो कोई किसान कर्जे में नहीं डूबेगा व न ही आत्महत्या करेगा। *